



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 26 मार्च, 2003/5 चैत्र, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 26 मार्च, 2003

संख्या : वि० स० - विधायन - अनु० बजट/1-22-2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक-1) जो आज

दिनांक 26 मार्च, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,

सचिव,

हि0प्र0 विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिप्रय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2003 है । संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियां जिनका योग 4,91,28,25,800 रुपये (चार अरब, इकानवें करोड़ अठाईस लाख, पच्चीस हजार, आठ सौ रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 2002—2003 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा । हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2002—2003 के लिए 4,91,28,25,800 रुपए की और राशि जारी करना ।
3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्ति सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा । विनियोग

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
1.	विधान सभा (राजस्व)	90,28,000	—	90,28,000
2.	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् (राजस्व)	75,00,000	—	75,00,000
3.	न्याय प्रशासन (राजस्व)	5,60,21,000	75,85,000	6,36,06,000
	और निर्वाचन (पूँजी)	40,00,000	—	40,00,000
4.	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	2,04,14,000	1,08,00,000	3,12,14,000
5.	भू-राजस्व (राजस्व)	15,86,05,000	—	15,86,05,000
	और जिला प्रशासन			
6.	आबकारी और कराधान (राजस्व)	12,48,000	—	12,48,000
7.	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	1,75,25,245	—	1,75,25,245
8.	शिक्षा (राजस्व)	12,29,79,000	—	12,29,79,000
	(पूँजी)	40,00,000	—	40,00,000
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	5,67,55,000	4,83,569	5,72,38,569
	(पूँजी)	2,64,00,000	—	2,64,00,000
10.	लोक निर्माण— (राजस्व)	1,20,000	—	1,20,000
	भवन (पूँजी)	8,000	—	8,000
11.	कृषि (राजस्व)	5,44,68,000	—	5,44,68,000
	(पूँजी)	7,28,00,000	—	7,28,00,000
12.	उद्यान (राजस्व)	6,95,01,000	—	6,95,01,000
13.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (राजस्व)	3,51,000	—	3,51,000
	(पूँजी)	8,31,000	—	8,31,000
14.	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व)	2,76,79,300	—	2,76,79,300
15.	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व)	12,89,000	—	12,89,000
16.	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	99,71,48,600	2,27,474	99,73,76,074
	(पूँजी)	11,39,000	—	11,39,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
17.	सड़कें और पुल (राजस्व)	1,20,000	—	1,20,000
	(पूँजी)	49,98,000	1,50,35,445	2,00,33,445
18.	आपूर्ति, उद्योग और (राजस्व)	15,10,89,381	—	15,10,89,381
	खनिज (पूँजी)	1,72,35,000	—	1,72,35,000
19.	सामाजिक सुरक्षा और (राजस्व)	2,52,00,600	2,05,413	2,54,06,013
	कल्याण (पोषाहार सहित)			
20.	ग्रामीण विकास (राजस्व)	2,44,23,000	—	2,44,23,000
22.	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	55,20,620	—	55,20,620
23.	जल और विद्युत (राजस्व)	22,61,62,090	—	22,61,62,090
	विकास (पूँजी)	86,87,00,000	—	86,87,00,000
24.	मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व)	1,06,45,000	—	1,06,45,000
25.	सड़क और जल परिवहन (राजस्व)	43,32,00,000	—	43,32,00,000
	(पूँजी)	16,000	—	16,000
26.	पर्यटन और नागर विमानन (पूँजी)	—	59,00,000	59,00,000
27.	श्रम, रोजगार और (राजस्व)	44,12,800	3,88,263	48,01,063
	प्रशिक्षण			
28.	जलापूर्ति, सफाई, आवास (राजस्व)	46,61,25,000	—	46,61,25,000
	और नगर विकास (पूँजी)	65,80,67,000	—	65,80,67,000
29.	वित्त (राजस्व)	5,29,50,000	—	5,29,50,000
	(पूँजी)	15,00,00,000	2,000	15,00,02,000
30.	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)	20,87,000	—	20,87,000
	(पूँजी)	10,00,000	—	10,00,000
31.	जनजातीय विकास (राजस्व)	75,05,000	—	75,05,000
	(पूँजी)	5,29,32,000	—	5,29,32,000
	कुल जोड़	4,87,21,98,636	4,06,27,164	4,91,28,25,800
	(राजस्व)	3,01,00,72,636	1,96,89,719	3,02,97,62,355
	(पूँजी)	1,86,21,26,000	2,09,37,445	1,88,30,63,445

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

दिनांक: 26 मार्च, 2003.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

वित्त विभाग, नस्ति संख्या फिन0ए0सी0(2) - 17 / 2002

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2003.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Short title. Act, 2003.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 4,91,28,25,800/- (Four hundred ninety one crores, twenty eight Lakhs, twenty five thousand, eight hundred rupees) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2002-2003 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of a further sum of Rs. 4,91,28,25,800 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2002-2003.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

Appropriation.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

1	2	3		
		Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Vidhan Sabha (Revenue)	90,28,000	—	90,28,000
2.	Governor and Council of Minister (Revenue)	75,00,000	—	75,00,000
3.	Administration of (Revenue)	5,60,21,000	75,85,000	6,36,06,000
	Justice and Election (Capital)	40,00,000	—	40,00,000
4.	General Adminis- (Revenue)	2,04,14,000	1,08,00,000	3,12,14,000
	tration			
5.	Land Revenue (Revenue)	15,86,05,000	—	15,86,05,000
	and District Adminis- tration			
6.	Excise and Taxation (Revenue)	12,48,000	—	12,48,000
7.	Police and Allied (Revenue)	1,75,25,245	—	1,75,25,245
	Organisations			
8.	Education (Revenue)	12,29,79,000	—	12,29,79,000
	(Capital)	40,00,000	—	40,00,000
9.	Health and Family (Revenue)	5,67,55,000	4,83,569	5,72,38,569
	Welfare (Capital)	2,64,00,000	—	2,64,00,000
10.	Public Works- (Revenue)	1,20,000	—	1,20,000
	Building (Capital)	8,000	—	8,000
11.	Agriculture (Revenue)	5,44,68,000	—	5,44,68,000
	(Capital)	7,28,00,000	—	7,28,00,000
12.	Horticulture (Revenue)	6,95,01,000	—	6,95,01,000
13.	Irrigation and Flood (Revenue)	3,51,000	—	3,51,000
	Control (Capital)	8,31,000	—	8,31,000
14.	Animal Husbandry (Revenue)	2,76,79,300	—	2,76,79,300
	and Diary Develop- ment and Fisheries			
15.	Planning and Back- (Revenue)	12,89,000	—	12,89,000
	word area Sub-Plan			
16.	Forest and Wild (Revenue)	99,71,48,600	2,27,474	99,73,76,074
	Life (Capital)	11,39,000	—	11,39,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
17.	Roads and Bridge (Revenue)	1,20,000	—	1,20,000
	(Capital)	49,98,000	1,50,35,445	2,00,33,445
18.	Supplies, Industries (Revenue)	15,10,89,381	—	15,10,89,381
	and Minerals (Capital)	1,72,35,000	—	1,72,35,000
19.	Social Security and (Revenue)	2,52,00,600	2,05,413	2,54,06,013
	Welfare (including Nutrition)			
20.	Rural Development (Revenue)	2,44,23,000	—	2,44,23,000
22.	Food and Ware (Revenue)	55,20,620	—	55,20,620
	housing			
23.	Water and Power (Revenue)	22,61,62,090	—	22,61,62,090
	Development (Capital)	86,87,00,000	—	86,87,00,000
24.	Printing and (Revenue)	1,06,45,000	—	1,06,45,000
	Stationery			
25.	Road and Water (Revenue)	43,32,00,000	—	43,32,00,000
	Transport (Capital)	16,000	—	16,000
26.	Tourism and Civil (Capital)	—	59,00,000	59,00,000
	Aviation			
27.	Labour Employ- (Revenue)	44,12,800	3,88,263	48,01,063
	ment and Training			
28.	Water Supply, (Revenue)	46,61,25,000	—	46,61,25,000
	Sanitation, Housing (Capital)	65,80,67,000	—	65,80,67,000
	and Urban Develop- ment			
29.	Finance (Revenue)	5,29,50,000	—	5,29,50,000
	(Capital)	15,00,00,000	2,000	15,00,02,000
30.	Miscellaneous (Revenue)	20,87,000	—	20,87,000
	General Services (Capital)	10,00,000	—	10,00,000
31.	Tribal Development (Revenue)	75,05,000	—	75,05,000
	(Capital)	5,29,32,000	—	5,29,32,000
	Grand Total	4,87,21,98,636	4,06,27,164	4,91,28,25,800
	(Revenue)	3,01,00,72,636	1,96,89,719	3,02,97,62,355
	(Capital)	1,86,21,26,000	2,09,37,445	1,88,30,63,445

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2002-2003.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 26th March, 2003.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A.C. (2)-17/2002]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2003 recommends, under article 207 of the Constitution of India the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.